# छात्र केंद्रित नई शिक्षा नीति

**सुश्री.श्रीदेवी बबन वाघमारे** कमला कॉलेज,कोल्हापुर| ई-मेल- shrideviwaghamare1993@gmail.com

---

शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है- सीखने एवं सिखाने की क्रिया जो मनुष्य के जीवन में अविरत चलती है| बचपन से लेकर मनुष्य के मृत्यु तक अपने परिचय में आए व्यक्ति एवं अपने आसपास के परिवेश से वह कुछ ना कुछ सीखता है और अपने आप को और मजबूत बनाता है| शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जिसका कोई उद्देश होता है और जिसमें मनुष्य अपने आंतरिक एवं बाह्य विकास को पूर्ण करता है| शिक्षा द्वारा ही मनुष्य की मानसिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और वह एक योग्य नागरिक बनता है।

शिक्षा के लिए पहली नीति 1968 में प्रख्यापित की गई थी और दूसरी 1986 में लागू की गई थी। NEP 2020 का लक्ष्य 2040 तक एक कुशल शिक्षा प्रणाली बनाना है, जिसमें सभी शिक्षार्थियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पहुंचाना है| मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय के द्वारा एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव लाया गया है और यह बदलाव इस्रो के प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में किया गया है| नैशनल एजुकेशन पॉलिसी की तहत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नई नीति तैयार की है जिसके अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र में काफी सारे बदलाव किए हैं नैशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है और यह पॉलिसी 2023 तक पूर्व विद्यालय माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में इसे लागू करना है| इसके पहले 10+2 का पैटर्न था जो इस नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न स्कूलों में लागू किया जाएगा।

नैशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य है कि, भारत में दी जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना जिससे भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सके| नई शिक्षा नीति में काफी सारे बदलाव किए है| जिसके कारण छात्र अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।इस क्रम में **कर्नाटक** देश का पहला राज्य है जहां एनईपी 2020 को लागू किया गया है। कर्नाटक सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू करने की घोषणा राज्य शिक्षा मंत्री डॉ. सीएन अश्वथ नारायण द्वारा 7 अगस्त 2021 को की गयी थी

**नई शिक्षा के सिद्धांत :**

- प्रत्येक छात्र की क्षमता की पहचान कराना और क्षमता का विकास करना|
- साक्षरता एवं संख्यात्मक ता के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना|
- शिक्षा को लचीला बनाना|
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना
- बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना|
- उच्च स्तर पर शोध कराना| तकनीकी का यथासंभव उपयोग पर जोर देना|
- छात्रों के मूल्यांकन पर ध्यान देना|
- विविध भाषाएं सिखाना छात्रों की सोच को रचनात्मक एवं तार्किक करना।

**नैशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं:**

• विद्यालयों में यह तय करना होगा कि मिल्क मिड-डे-मील की गुणवत्ता ठीक हो जिसके कारण बच्चों को लंच बॉक्स लाना ना पड़े|

• सुविधा ठीक तरीके से उपलब्ध होने चाहिए जिससे कि बच्चे को वाटर बोतल नहीं लाना पड़े। इन सुविधाओं के कारण स्कूल बैग का साइज छोटा हो जाएगा।

• नैशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बच्चों के होमवर्क पर भी ध्यान दिया जाएगा| इसके अंतर्गत दूसरी कक्षा तक के बच्चों को कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा| क्योंकि पहली और दूसरी कक्षा के छात्र बहुत छोटे होते हैं और उन्हें इतनी देर बैठने की आदत नहीं होती| कक्षा तीसरी और चौथी पांचवी के बच्चों को प्रत्येक हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा तथा कक्षा छठी से लेकर आठवीं के बच्चों को प्रतिदिन 1 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा और 9वीं से 12वीं की क्लास के बच्चों को प्रतिदिन 2 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा।

**नैशनल एजुकेशन पॉलिसी की विशेषताएं**

• मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय अप शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा|

• नैशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा जिसमें मेडिकल और विधि की पढ़ाई भी शामिल की गई है|

• पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था परंतु अब नई पॉलिसी के अंतर्गत 5+3+3+4 का पाटन में फॉलो किया जाएगा| जिससे कि 12 साल की स्कूल शिक्षा होगी और 3 साल की फ्री स्कूल शिक्षा होगी|

• छठी कक्षा से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण इंटरशिप आरंभ कर दी जाएगी|

• पांचवी कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी|

• पहले विज्ञानं, वाणिज्य और कला शाखाएं होती थी| लेकिन अब ऐसी कोई शाखाएं नहीं होगी| छात्र अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी विषय चुन सकते हैं| छात्र फिजिक्स के साथ-साथ अकाउंट का भी, या आर्ट्स का कोई भी विषय पढ़ सकते हैं।

• छात्रों को छठी कक्षा से ही कोडिंग सिखाया जाएगा| सभी स्कूल में डिजिटल इक्विटी किए जाएंगे सभी प्रकार की परिभाषाओं को क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट किया जाएगा|

• वर्चुअल लैब का विकास किया जाएगा।

**नैशनल एजुकेशन पॉलिसी की मुख्य बातें**

• उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ कई पर विस्तार और विकास बिंदु होगी

• स्नातक कोर्स 3 या 4 साल की हो सकते हैं जिसमें कई सारे एग्जिट ऑप्शन होंगे और वह भी उचित सर्टिफिकेशन के साथ| जैसे कि यदि छात्र ने 1 साल का स्नातक कोर्स की पढ़ाई की तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के बाद एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल के बाद डिग्री दी जाएगी और 4 साल के बाद रिसर्च के साथ बैचलर की डिग्री दी जाएगी।

• एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जाएगा जिससे कि छात्रों के द्वारा अर्जित किए गए डिजिटल अकैडमी क्रेडिट हो या विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से उन्हें संग्रहित किया जाएगा इसे अंतिम डिग्री के लिए स्थानांतरित किया जाएगा और गिना जाएगा।

• लर्निंग पर जोर देकर पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता को कम किया जाएगा और नई एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य हैं।

**नैशनल एजुकेशन पॉलिसी के लाभ :**

• नैशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा|

• पढ़ाई में संस्कृत और भारत की अन्य प्राचीन भाषाएं पढ़ने का ऑप्शन भी रखा जाएगा छात्र अगर चाहे तो या भाषा पड़ सकता है|

• बोर्ड परीक्षाओं में भी बदलाव किए जाएंगे|

• पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा|

• उच्च शिक्षा में में एमफिल की डिग्री को खत्म किया जाएगा।

• नैशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनके कौशल पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा|

• नई शिक्षा नीति के तहत यदि कोई छात्र कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहता है तो पहले कोर्स की निश्चित समय तक ब्रेक लिख सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है।

**नैशनल एजुकेशन पॉलिसी के चार चरण**

नैशनल एजुकेशन पॉलिसी कुछ चार चरणों में विभाजित कर दी है जो 5+3+3+4 इस नए पैटर्न में 12 साल की स्कूल शिक्षा और 3 साल की फ्री स्कूल शिक्षा शामिल कर दी है| नैशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी सरकारी एवं प्राइवेट दोनों संस्थानों को फॉलो करना आवश्यक है। नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के चार चरण को कुछ इस प्रकार बांटा गया है-

• फाउंडेशन स्टेट - फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए जिसमें 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा तथा 2 साल की स्कूली शिक्षा शामिल है फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत भाषा कौशल और शिक्षण के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

• प्री प्राइमरी स्टेज - अंतर्गत 8 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे आएंगे जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा इस देश में बच्चों को भाषा और संख्यात्मक कौशल विकास करना शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा इस देश में बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा।

• मिडिल स्टेज स्टेज - इस के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे आएंगे कक्षा 6 से बच्चों को कोड़ीग सिखाई जाएगी और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ इंटर्नशिप भी प्रदान की जाएगी।

• सेकेंडरी स्टेज - इसके अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे आएंगे जैसे कि पहले बच्चे विज्ञानं, कला और वाणिज्य आदि शाखाएं चुन लेते थे| परंतु अब यह खत्म कर दिया गया है| अब बच्चे अपनी पसंद का विषय चुन ले सकते हैं| जैसे कि बच्चे विज्ञानं के साथ वाणिज्य या फिर कला शाखा के भी विषय ले सकते हैं।

**नई शिक्षा नीति 2022 में नए बदलाव**

• न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत छात्रों को अब कोई एक शाखा नहीं छोड़नी होगी अब छात्र कला शाखा के साथ साइंस भी पढ़ सकते हैं या साइंस शाखा के साथ-साथ 8 शाखा में भी पढ़ सकते हैं प्रत्येक विषय को अतिरिक्त पाठ्यक्रम ना मान की पाठ्यक्रम के रूप में देखा जाएगा जिसमें योग खेल नृत्य मूर्तिकला संगीत आदि शामिल है शारीरिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा वोकेशनल एवं एकेडमी शाखा को अलग नहीं किया जाएगा जिससे की छात्रों को दोनों क्षमताओं को विकसित करने का मौका मिले।

• B.ed अब 4 साल का नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंतर्गत B.ed को 4 साल का कर दिया गया है 2030 के अंत तक शिक्षक की न्यूनतम योग्यता 4 साल का B.ed प्रोग्राम होगी।

• वोकेशनल स्टडीज पर फोकस - हमारे देश में वोकेशनल स्टडीज सीखने वाले छात्र 5% से भी कम है| इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा छठी से कक्षा आठवीं तक के बच्चों को वोकेशनल स्टडीज सीखने पर ध्यान दिया जाएगा| जिसमें बागबानी, लकड़ी का काम, मिट्टी का बर्तन,बिजली का काम आदि शामिल है| 2025 के अंत तक नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कम से कम 50% छात्रों को वोकेशनल स्टडीज पढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

• मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को यदि उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए तो वह बात को ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे| इस बात को ध्यान में रखते हुए नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंतर्गत पांचवी क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने का प्रावधान रखा गया है| पाठ्य पुस्तकों को भी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा| शिक्षक और छात्रों के बीच का बातचीत का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होगी।

निष्कर्ष के रूप में नई शिक्षा नीति छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी| केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा प्रणाली में बदलाव किए हैं जिसके कारण भारत एक ज्ञान का महाशक्ति केंद्र बनकर सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत होगा| नई शिक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है| स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्रीडी मशीन डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में भी कुशल छात्र तैयार होंगे और युवाओं को रोजगार की क्षमता में वृद्धि प्रधान होगी| इसी कारण यह नई शिक्षा प्रणाली आज के युग में प्रासंगिक है यह शिक्षा प्रणाली छात्र केंद्रित है जो छात्रों के लिए उनके भविष्य के लिए रोजगार वृद्धि के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

संदर्भसूचि

1. http://www.sarkariyojana.com>new-education-policy
2. http://www.drishtiias.com>new-education-policy
3. http://www,amarujala.com>education